

राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति, 2017 –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक व पद्मविभूषण डॉ. के कस्तूरीरंग की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, इसकी रिपोर्ट 31 मई, 2019 को आई।

यह नीति मौजूदा शिक्षा प्रणाली की निम्न चुनौतियों को लक्षित करती है – (1) पहुंच, (2) समानता, (3) क्वालिटी, (4) वहन करने योग्य, (5) जवाबदेही।

इससे पहले वर्ष 2015 में कैबिनेट सचिव, टी. एस. आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसके द्वारा प्रस्तुत मसौदा किसी कारणों की वजह से अनुकूल नहीं था।

नई शिक्षा नीति के प्रमुख तथ्य –

- स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के साथ ही कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया है।
- नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाते हुए अब 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इस कानून के दायरें में लाया गया है।

- इस कानून के दायरे में प्राथमिक पूर्व शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए कानून लागू करने की सिफारिश की गई है।
- नई नीति में 12वीं कक्षा के अध्ययन को 5 + 3 + 3 + 4 के फॉर्मूले के तहत चार चरणों में बांटने की बात कही गई—
 - i. पहला चरण (Foundation Stage) 3 to 8yr
 - ii. दूसरा चरण (Preparatory Stage) 8 to 11yr
 - iii. तीसरा चरण (Middle Stage) 11 to 14yr
 - iv. चतुर्थ चरण (Secondary Stage) 14 to 18yr
- नई शिक्षा नीति के प्रारूप में 'राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण' बनाने का सुझाव।

- निजी स्कूलों के नाम से 'पब्लिक' शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध का सुझाव।
- प्राथमिक व इससे उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य।
- प्राथमिक पूर्व शिक्षा तक पहुँच व शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 30 : 1 रखने का लक्ष्य।
- पौष्टिक आहार की व्यवस्था का प्रावधान।
- मिड-डे मील के कार्यक्रम का विस्तार करने का सुझाव।
- कमजोर विद्यार्थियों हेतु रेमेडियल शिक्षण की व्यवस्था। यह कक्षाएं त्रैमासिक परीक्षाओं में D और E ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए होगी जो नियमित शिक्षकों द्वारा ली जाएगी।

- नवान्मेषी शिक्षण उपायों को अपनाने का सुझाव जिसके तहत भाषा, गणित व लेखन कौशल पर जोर तथा भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन शामिल है।
- बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से जोर व आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय स्कूलों जैसी व्यवस्था का सुझाव।
- शिक्षा में शिक्षकों की सुविधाओं हेतु तकनीक प्रयोग पर बल।
- शिक्षा के दौरान विषय-वस्तु का बोझ कम करने के सुझाव ताकि विद्यार्थियों की तर्क शक्ति मजबूत की जा सके।

- विषयवस्तु को कम करने के लिए वर्ष 1993 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यशपाल समिति की रिपोर्ट “The Learning without Burden” का हवाला दिया गया है।
- स्तरहीन शिक्षा संस्थानों को बंद करने का सुझाव।
- नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव, जिसका दक्षिणी राज्यों में विरोध हुआ।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की सिफारिश।
- समावेशी व न्यायसंगत शिक्षण प्रणाली विकसित करना।

- वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता चार वर्षीय लिबरल इंटरग्रेटेड B.Ed. डिग्री होगी।
- नई नीति के तहत वर्ष 2022 तक स्कूली पाठ्यक्रम व शिक्षण के तरीके में बदलाव किया जाएगा।
- डिजिटल साक्षरता जैसी 21वीं सदी के कौशल का विकास।
- वर्ष 2025 तक तीन से छह वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण व विकास के लिए उपयुक्त देखभाल व शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य।

Dr. Mukesh Pathani

- उत्कृष्ट छात्रों को मैरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।
- योग्यता व ज्ञान की बेहतर परख के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में सुधार का सुझाव।
- वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- बहुविषयक संस्थान जो भारत में उच्च शिक्षा समता विकास व समान रूप से आमजन की पहुंच में होंगे।
- छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए कल्पनाशील व व्यापक तौर पर उदार शिक्षण व्यवस्था बनाने की पहल।

- भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाली, पार्सियन व प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना।
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन।
- सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान वोकेशनल एजुकेशन कोर्स व प्रोग्राम संचालित करेंगे।
- सभी निजी व सार्वजनिक संस्थान नियामक व्यवस्था के तहत संचालित होंगे।
- शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है।
- वर्ष 1986 में तैयार शिक्षा नीति में वर्ष 1992 में व्यापक संशोधन किया गया और यह नीति अबतक प्रचलन में है।

Higher Education

MCQ

Dr. Mukesh Pancholi

1. विद्यार्थियों की तर्कशक्ति मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 के मसौदे में बल दिया गया -

(A) गणनाम समिति की सिफारिशों पर

(B) यशपाल समिति, 1992

(C) यशपाल समिति, 2009

(D) जनार्दन राम रेड्डी समिति

Dr. Mukesh Pancholi

2. (I) अध्यक्ष-डॉ. के कस्तूरीरंग।

(II) स्कूली व उच्च शिक्षा के साथ-साथ कृषि व तकनीकी शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया जाए।

(III) इस शिक्षा नीति में प्राथमिक से लेकर 10वीं तक की कक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई है।

नयी शिक्षा नीति, 2017 से संबंधित कथनों को

पहचानिए -

(A) I, III

(B) I

(C) I, II

(D) उपरोक्त सभी

3. (A) वर्तमान परिपेक्ष्य के अनुसार शिक्षा में गुणवत्ता व सार्वभौमिक पहुंच जैसी अभी भी गंभीर समस्याएं हैं।

(R) नई शिक्षा नीति, 2017 में प्राथमिक पूर्व शिक्षा से 12वीं कक्षा तक पर यह कानून लागू करने की सिफारिश की है, साथ ही एक राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है।

(A) A व R सही हैं, R, A की सही व्याख्या करता है।

(B) A व R सही हैं, परन्तु स्पष्ट व्याख्या नहीं करता।

(C) A गलत परन्तु R सही है।

(D) R गलत परन्तु A सही है।

4. (I) शिक्षा नीति, 2017 में 12वीं कक्षा तक के अध्ययन को 5 + 5 + 2 में बांटा गया है।

(II) शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 30 : 1 रखने का लक्ष्य।

(III) रेमेडियल शिक्षण व्यवस्था।

उपरोक्त में से कौन-सा / से कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 से संबंधित है -

(A) I, II

(B) केवल II

(C) केवल III

(D) II, III

5. रेमेडियल शिक्षण व्यवस्था की जाएगी (शिक्षा नीति, 2017 के अनुसार) -

(A) C, D ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए

(B) D, E ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए

(C) अनुत्तीर्ण बच्चों के लिए

(D) मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए

Dr. Mukesh Patholi

6. (I) पूर्व प्राथमिक से 12 तक की कक्षा को शिक्षा नीति के दायरे में लाना।
- (II) RTE को व्यापक बनाते हुए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इसके दायरे में लाना।
- (III) राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण का गठन।
- (IV) GER को 2035 तक मिनिमम 35% तक बढ़ाने का लक्ष्य।

उपरोक्त तथ्य संबंधित है -

- (A) शिक्षा नीति, 1968
- (B) शिक्षा नीति, 1986
- (C) शिक्षा नीति, 2017
- (D) शिक्षा नीति, 2015

7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या करने की सिफारिश शिक्षा नीति, 2017 में की गई है -

(A) शिक्षा मंत्रालय

(B) शिक्षा आयोग

(C) मानव नियुक्ति आयोग

(D) गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मंत्रालय

Dr. Mukesh Pancholi

8. (I) वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण व विकास के उचित देखभाल व शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य।

(II) 2025 तक शिक्षण के न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय लिबरल इंटीग्रेटेड B.Ed. डिग्री होगी।

उपरोक्त में से शिक्षा नीति, 2017 से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए -

(A) कथन I, II दोनों सही हैं।

(B) कथन I सही है, II गलत है।

(C) कथन II सही है, I गलत है।

(D) कथन I, II दोनों गलत हैं।

9. मुफ्त में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत वर्ष में शुरू किया गया था -

(A) 1947 से

(B) 1964 से

(C) 1968

(D) 1986

Dr. Mukesh Pancholi

10. शिक्षक शिक्षा को तकनीकी शिक्षा माना जाता है -

(A) अमेरिका

(B) यूके

(C) इंग्लैण्ड

(D) भारत

Dr. Mukesh Pancholi

11. माध्यमिक स्तर में शिक्षक शिक्षा के लिए रिफ्रेशर कोर्स संचालित किए जाते हैं –

(A) राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा

(B) शैक्षणिक स्टॉफ कॉलेज

(C) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान

(D) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

Dr. Mukesh Pancholi

12. समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है -

- (A) सीखने की बाधाओं को उजागर करना व कम करना।
- (B) सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवहार, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम व वातावरण को बदलने के लिए।
- (C) समाज के विभिन्न समुदायों की स्थानीय संस्कृतियों व सामग्रीयों को लगातार बढ़ावा देने के लिए।
- (D) उपरोक्त सभी।

13. (I) 2020 तक स्कूली पाठ्यक्रम व शिक्षण के तरीकों में बदलाव।

(II) उत्कृष्ट छात्रों को मैरिट बेस्ड स्कॉलरशिप।

(III) त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिन्दी भाषा अनिवार्य।

उपरोक्त में से शिक्षा नीति, 2017 से संबंधित तथ्यों को छांटिए -

(A) I, II

(B) II, III

(C) उपरोक्त सभी

(D) इनमें से कोई नहीं

14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 के अनुसार, PM की अध्यक्षता में गठित संस्थान -

(A) राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण

(B) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

(C) बहुविषयक संस्थान

(D) राष्ट्रीय भाषा संस्थान

Dr. Mukesh Pancholi

15. शिक्षा नीति, 2017 से संबंधित सही कथन को चुनिए-

I. बहुविषयक संस्थान जो उच्च शिक्षा समता विकास व समान रूप से आमजन की पहुंच में होंगे।

II. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कि TET को बेहतर बनाएगा।

III. सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान वोकेशनल एजुकेशन कोर्स संचालित करेंगे।

(A) I, II

(B) I, II, III

(C) II, III

(D) I, III